



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट-<http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाषनं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्सनं. - 0755-2462136

No: 532/SEIAA/2025

Date: 25/05/2025

प्रति,

Shri Vishal Shivhare,

R/o Mig-2, Shopping Centre, Tila Jamalpur,

District- Bhopal (M.P.)

E-mail - vishalec2023@gmail.com

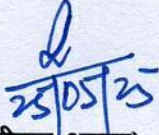
विषय :- Proposal No. SIA/MP/MIN/462629/2024- Case No P2/889/24 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), for Production Capacity of Stone - 63,840 m3/year & M sand- 63,840 m3/year, in an area of 4.00 ha., Khasra No. 23/2/1, 23/2/2, Village- Dillod, Tehsil- Berasiya, Dist.- Bhopal (M.P.) by Shri Vishal Shivhare, R/o Mig-2, Shopping Centre, Tila Jamalpur, District- Bhopal (M.P.)

विषयान्तर्गत प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 761वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित पर्यावरण अनुमति प्रदान किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण दिनांक 03.06.2024 को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को अग्रेषित किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण SEIAA की बैठक में विचारण नहीं होने के कारण 45 दिवस से अधिक की अवधि समाप्त हो गई है।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के पैरा 8 की कंडिका (iii) इस प्रकार है - "In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in subparagraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned."

अतः ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार उक्त प्रकरण में SEAC की 761वीं बैठक दिनांक 30.05.2024 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को अंतिम निर्णय मानते हुए राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा "Deemed Approval" माना जाकर पर्यावरण अनुमति दी जाती है। तदनुसार प्रकरण में ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार आगामी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आप स्वतंत्र हैं।

(प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमोदित)


(श्रीमन् शुक्ला)

कार्यपालन संचालक, एप्लो
एवं सदस्य सचिव, SEIAA

A

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
4. अध्यक्ष, SEIAA, एम्को पर्यावरण परिसर भोपाल (म.प्र.)।
5. अध्यक्ष SEAC, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)।
6. सदस्य सचिव, SEAC एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल।
7. कलेक्टर, जिला भोपाल (म.प्र.)।
8. वन मंडलाधिकारी, जिला भोपाल (म.प्र.)।
9. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
10. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
11. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल (म.प्र.)।
12. संबंधित फाईल।

की ओर सूचनार्थ।



कार्यपालन संचालक, एम्को
एवं सदस्य सचिव, SEIAA



761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. Case No P2/889/24 Shri VISHAL SHIVHARE, Project Proponent, Mig-2, Shopping Centre, Tila Jamalpur, District- Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Gitti and M sand in an area of 4.00 ha.) (Gitti – 63,840 m³ & M sand- 63,840 m³) (Khasra No. 23/2/1, 23/2/2) Village- Dillod, Tehsil- Berasiya, Dist.- Bhopal (M.P.) SIA/MP/MIN/462629/2024 (B-2) Expansion

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनःमूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री विशाल शिवहरे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s. Hariom Stone Crusher, Prop. Shri Vishal Shivhare R/o- MIG, Shopping Centre, Tila Jamalpura, Dist. Bhopal (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	23/2/1, 23/2/2 (Pvt. land), –नॉन फॉरेस्ट लैंड), Area -4.00ha
स्थल	Village- Dillod, Tehsil- Berasiya, Dist.- Bhopal Madhya Pradesh
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल म.प्र. के पत्र क्रमांक 2021-22/खनिज/उ.प./न.क्र.32/2019, दिनांक 12/02/2020 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	पर्यावरणीय स्वीकृति क्षमता विस्तार (EC Expansion)
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	यह प्रकरण EC Expansion का है। पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार उत्पादन क्षमता स्टोन— 61,348घनमीटर/वर्ष व कोपरा— 15,400घनमीटर/वर्ष है। तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा विस्तार उत्पादन क्षमता स्टोन – 63,840 घनमीटर/वर्ष और एम सैंड— 63,840 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन – 63,840 घनमीटर/वर्ष और एम सैंड— 63,840 घनमीटर/वर्ष है।)
टॉर	Not Applicable B2 project
सिया ई.सी. का विवरण	EC Letter No. – 3598/SEIAA/2020 File No. – 7488/2020 Date of Issue EC – 14.10.2020 (Area-4.00ha, Production Capacity for Stone- 61,348Cum/Year & for Kopra- 15,400Cum/Year)

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 172/खनिज/2024 भोपाल दिनांक 31/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान संचालित/स्वीकृति नहीं है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 172/खनिज/2024 भोपाल दिनांक 31/01/2024 अनुसार 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 172/खनिज/2024 भोपाल दिनांक 31/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवब साइट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवेलाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दिल्लोद जिला भोपाल के पत्र क्रमांक क्यू दिनांक 07/10/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज में स्थित पेड़ों का विवरण-3। पेड़ काटा नहीं जायेगा
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा में कच्चा रोड 433 मीटर पर
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	प्रस्तावित खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ क्रमांक- 45 में सरल क्र. 148 में है।
जनसुनवाई	लागू नहीं है।

सिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति	टिप्पणी
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। 961मीटर में से 481मीटर फेंसिंग की गई है।	अपूर्ण फेंसिंग 481 मीटर की लागत राशि ई.एम.पी. में शामिल कर ला गई है। जो पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के 6 महीने के अन्दर कर दी जायेगी।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। 4820 पौधों में से 3700 पौधों बैरिया जोन में लगाये जा चुका है।	पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के 6 महीने के अन्दर बचे हुए 1120 पौधे ग्राम दिल्लोद के ग्रामीणों में वितरित करवा दिये

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

		जायेंगे। जिसकी लागत राशि ई.एम.पी. में शामिल कर ली गई है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। 45 मीटर गारलेण्ड ड्रेन बनवाया गया है। सेटलिंग टैंक नहीं बना है।	गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की लागत राशि ई.एम.पी. में शामिल कर ला गई है। जो पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के 6 महीने के अन्दर कर दी जायेगी।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम दिल्लोद के शासकिय स्कूल में रगाई पुताई का कार्य, टाईल्स लगवाने का कार्य व बच्चों के लिए बैग आदि का वितरण किया गया है। जिसमें 1,20,000 में से राशि 97,890 रु खर्च किया गया है।	सामाजिक कार्य के लिए बची हुई राशि का कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के 6 महीने के अन्दर कर दी जायेगी।
पीपी को वृक्षारोपण और प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण वाली एक लॉग बुक भी रखनी चाहिए और पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वनस्पतियों को कोई नुकसान न हो	लॉग बुक मेंटेंन नहीं की गई।	हम वचन देते हैं कि लॉग बुक मेंटेंन करेंगे।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार चारागाह विकास की स्थिति	चारागाह का विकास नहीं किया गया है।	हम हमारी खदान के आस-पास शासकिय भूमि में चारागाह का विकास ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जायेगा। जिसकी लागत राशि ई.एम.पी. में शामिल कर ली गई है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि सिया द्वारा पत्र क्रमांक 3598 दिनांक 14/10/22 में ई.सी. जारी की गई थी। पूर्व में जारी ई.सी. में दी गई शर्तों के पालन में फेंसिंग कार्य 80 प्रतिशत, बैरियर जोन में 7.5 मी. पर 3700 पौधों का रोपण व सामाजिक कार्य के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। चारागाह विकसित नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक को चारागाह विकसित करने, लॉगबुक प्रस्तुत करने, प्रमाणीकरण पत्र, पूर्व में जारी ई.सी. में दी गई शर्तों का बिन्दुवार लागत एवं व्यय की जानकारी प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिये गये। डी.जी.एम.एस. से प्रदाय की गई अनुमति की वैधता 02/06/2022 को समाप्त हो गई है, इसका नवीनीकरण कराया जाये एवं समिति ने निर्देश दिये कि Deep Hole drilling and Blasting की स्थिति में पृथक से डी.जी. एम. एस. से अनुमति लेना होगी। बिन्दु क्रमांक 3.3.1 व 3.3.2 पैरा में वर्षवार 2024-25 हेतु 5 बेंच का निर्माण होगा जिससे कुल

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 30 मई 2024

उत्पादन 1,27,680 क्यूबिक मीटर किया जावेगा । इस हेतु 30 मीटर गहराई माईनिंग प्लान में दी गई है, अभी तक खनन कार्य 13 मीटर गहराई तक हो चुका है । बैरियर जोन खुदा हुआ है जिसका रेस्टोरेशन किया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता- स्टोन – **63,840** घनमीटर/वर्ष और एम सैंड– 63,840 घनमीटर/वर्ष है ।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी ।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
5. पिट्स में बैचेस/बैरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे ।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे ।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कंपीटल राशि रु. 11.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 6.17 लाख प्रति वर्ष ।

SL.N	Particulars	Capital (inRs.)	Cost	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION				
1(a)	Water sprinkling though tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil		50,000
1 (b)	Cost of water of 4500 ltr.@0.15 Rs/liter for 300 days	NIL		2,02,500
2	Garland Drain is proposed (229m x 1.5m x 1.5m) Settling Tank is 15m x 04m x 2.5m (03 No.)	50,000		15,000
3	Pucca (WBM) Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (200mx 5m) @300/sqm	3,00,000		30,000
4	Barbed Fencing 50% @ (481m x Rs.300)	1,44,300		14,430
5	Plantation within 7.5 barrier zone @ Rs. 200/plant Total plantation –1500 Plants for One years 1500 xRs.200= Rs. 3,00,000/-	4,13,500		41,350
	Plantation within approach road@ Rs. 500/plant Total plantation 70 Plants for one years 70xRs.500= Rs 35,000/-			

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

	Plantation outside of lease @ Rs. 50/plant. Total plantation outside the lease area 3200Plants for Two (3200X Rs. 50)= Rs. 22,500/-		
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 75,000 for two locations/year	NIL	1,50,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler 10--11 labour@Rs.10,000/cooler)&Rs.2000/year for maintenance	Already Provided	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	Already Provided	10,000
9	Medical Check-up for 10-11 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	10,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	Already Provided	2,000
11	PPEs for other mining operations for 10-11 workers @ Rs. 1500/worker	Already Provided	2,000
12	Shelter rooms for labors (15*10) =150Square feet @Rs.800/square ft and gas cylinder with gas chulha .@9000	Already Constructed	12,900
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year Maintenance.	5,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for 29 trucks @1000/truck	NIL	58,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	50000	5000
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & Maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
16	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	crusher is not proposed within the lease	
17	Vocational Training for 10 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	5,000

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

19	Adoption of trees for carbon sequestration	50,000	5,000
20	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission.	20,000	-
21	Restoration of barrier zone and any other activity Related to mine	1,00,000	nil
	Total	11,69,800/-	617,180/-

8. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम दिल्लौद के ग्रामवासियों के लिए चिकित्सा अधिकारी से परामर्श कर आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में योगदान राशि जमा प्रथमवर्ष में किया जायेगा।	60,000 /—
योग	60,000/-

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
प्रथम वर्ष			
1	बैरियर जोन	इमली, कटहल, आम, अमरुद, बेल, जामुन एवं अन्य फलदार स्थानीय प्रजातियाँ,	1500
2	परिवहन मार्ग (200 मीटर) (पूर्ण सुरक्षा सहित)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	70
3	दिल्लौद ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, मुनगा, सीताफल अन्य फलदार स्थानीय प्रजातियाँ,	3200

761वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 मई 2024

4	शासकीय विद्यालय दिल्लौद	कचनार, पुत्ररंजीवा ,मौलश्री और कुसुम अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि।	30
---	-------------------------------	--	----

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. Case No P2/890/24 Shri AMIT VERMA, Lessee, R/o- H. No. 14/45, ward 14, Ashta Road Polay Kala, Shajapur, District-Shajapur, M.P. Prior Environment Clearance for Stone (Gitti), M sand and Murrum in an area of 2.00 ha.) (Stone (Gitti) – 10000 m3/Year, M-Sand – 5000 m3/Year, Murrum – 5200 m3/Year) (Khasra No. 1/8/4) Village - Polaykalan, Tehsil- Polaykalan, District- Shajapur (M.P.) SIA/MP/MIN/ 470514/2024 (B-2)

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 30.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमित वर्मा पिता श्री कुंदन वर्मा ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अमित वर्मा पिता श्री कुंदन वर्मा निवासी मकान नंबर 02 वार्ड नंबर 14 अपार्टा रोड पोलायकला जिला शाजापुर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	निजी भूमि-नॉन फॉरेस्ट लैंड) खसरा नं. 1/8/4	2.00 Hectare.
स्थल	ग्राम पोलायकला तहसील-पोलायकला जिला- शाजापुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 516/ खनिज/ 2024 दिनांक 12/03/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है,	

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 05 जून 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 05 जून 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.